हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 125 लखनऊ, बुधवार 24 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

उन्नाव रेप केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद सजा पर लगाई रोक, मिली सशर्त जमानत

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली/उन्नाव। उन्नाव रेप मामले के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। हालाँकि, कोर्ट ने कई सख्त शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत तुरंत रद्द हो जाएगी। हाईकोर्ट का यह फ़ैसला सेंगर द्वारा 2019 में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दिए जाने के मामले में आया है। कोर्ट ने साफ़ किया है कि यह राहत सिर्फ अपील लंबित रहने तक है। अपील का फैसला आने तक सजा निलंबित रहेगी। अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने आदेश दिया कि सेंगर को 15 लाख रुपये की निजी जमानत और इतनी ही राशि के तीन जमानतदार पेश करने होंगे।

कोर्ट ने क्या शर्तें लगाई

सेंगर पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकते।

पीड़िता या उनकी मां को किसी भी तरह की धमकी नहीं दे सकते।

अपील की सुनवाई के दौरान दिल्ली में ही रहना होगा।

अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा।

हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी।

अगर अपील में दोषी ठहराए गए तो बाकी सजा काटने के लिए उपलब्ध रहें।

जमानत के बावजूद जेल से रिहाई मुश्किल

हालाँकि रेप केस में सजा निलंबित हो गई है, लेकिन पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत वाले अलग केस में 10 साल की सजा अभी भी लागू है। उस केस में सेंगर की सजा निलंबित करने की अपील अलग से लंबित है। इसलिए फिलहाल सेंगर की जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। 10 साल की जेल के मामले में राहत मिलने के बाद ही वह जेल से रिहा हो पाएँगे। क़ानूनी जानकारों का कहना है कि जब तक दूसरा केस भी साफ़ नहीं होता, वे जेल में ही रहेंगे। पहले भी सेंगर को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी, जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए एम्स में। इस साल और पिछले साल भी ऐसी राहत मिली थी। मामला क्या है? यह केस 2017 का है। उन्नाव जिले के माखी गांव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके

कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था। पीड़िता ने जब शिकायत करने की कोशिश की तो उसके पिता को पुलिस हिरासत में पीट—पीटकर मार डाला गया। इस मामले में सेंगर पर पीड़िता के पिता की हत्या में साजिश रचने का भी आरोप लगा। हालाँकि, कार्रवाई में बहुत देरी की गई। आरोप लगा कि पीड़िता पर केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। जब यह मामला सुर्खियों में आया तो सेंगर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का दबाव बना। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त तक लिखा। सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए केस दिल्ली शिफ्ट किया था और रोजाना सुनवाई करके 45 दिनों में फैसला करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी संबंधित केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए थे। 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिसंबर में सेंगर को रेप के लिए उम्रकैद और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। तब से सेंगर जेल में हैं। बहरहाल, हाईकोर्ट का यह ताज़ा फ़ैसला महिलाओं के खिलाफ अपराधों और राजनीतिक प्रभाव वाले मामलों में न्याय व्यवस्था पर फिर से बहस छेड़ सकता है। पीड़िता पक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा है कि सेंगर जैसे प्रभावशाली लोग न्याय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पीड़िता पर हुए थे हमले उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसके परिवार पर हमले भी हुए। पीड़िता जब नाबालिग थी तो कुलदीप सिंह सेंगर के घर में उसका बलात्कार किया गया। 2018 में पीड़िता के पिता पर सेंगर के भाई और सहयोगियों द्वारा हमला किया गया। गंभीर चोटें लगीं। इसके बाद पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया और 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में उनकी मौत हो गई। हिरासत में उनकी पिटाई किए जाने का आरोप लगा और सेंगर पर साज़िश रचने का आरोप लगा। 2019 में पीड़िता, उनकी दो मौसियाँ और वकील कार से जा रहे थे जब रायबरेली में एक ट्रक ने टक्कर मारी। दो मौसियों की मौत हो गई, पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार ने इसे साजिश बताया।

भारत करेगा श्रीलंका की मदद, 450 मिलियन डॉलर चक्रवात राहत पैकेज देने का प्रस्ताव

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत चक्रवात दितवाहा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा है और उसने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है। जयशंकर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर श्रीलंका में हैं। उन्होंने श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरथ के साथ बातचीत में यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को मोदी का एक पत्र भी सौंपा। एस जयशंकर ने X पर पोस्ट किया, ष्चक्रवात दितवाह के दौरान श्रीलंका के साथ खड़े होने पर भारत को गर्व है। 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता पैकेज का प्रस्ताव वह दो दिन की श्रीलंका यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा ष्जैसे ही श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबर रहा था, इस प्राकृतिक आपदा ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि हम अब श्रीलंकाई सरकार के साथ मिलकर उनकी प्राथमिकताओं पर काम करें। इस संबंध में, हमने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता पैकेज प्रस्तावित किया है।

दो चरणों में होगी श्रीलंका की सहायता

उन्होंने कहा, इस पैकेज में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती क्रेडिट लाइन और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल होगा। इस पैकेज को श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारी सहायता में चक्रवात से सबसे

ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पहला, सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी का पुनर्वास और बहाली शामिल है। दूसरा, पूरी तरह से नष्ट हुए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण के लिए सहायता। तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के लिए सहायता, विशेष रूप से वे जो चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुई हैं। चौथा, कृषि, जिसमें अल्प और मध्यम अवधि में संभावित कमी को दूर करना शामिल है। और पांचवां, बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी की दिशा में काम करना। चक्रवात के पहले दिन से ऑपरेशन सागर बंधु सक्रिय जयशंकर ने कहा कि नुकसान के पैमाने को देखते हुए, यह स्वाभाविक था कि भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया। उन्होंने कहा कि भारत का ऑपरेशन सागर बंधु दितवाह के पहले ही दिन शुरू हो गया था। उन्होंने कहा, हमारा विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS उदयगिरि कोलंबो में मौजूद थे और उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर तैनात किए गए।

ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का हुआ खुलासा

एजेंसी

नई दिल्ली। डब्बा व्यापार/ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने सोमवार को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई और दुबई में अवैध रूप से डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों में लिप्त एक गिरोह के खिलाफ अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है। इस केस में 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता चला है। डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए एमटी5 सर्वरों व भूमिगत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। कई प्रख्यात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नकली ट्रेड दिखाए गए। गुमनाम खातों को एन्क्रिप्टेड संचार और नकद—आधारित निपटान के जरिए उपयोग में लाया गया। यह सब भी सीक्रेट तरीके से किया गया। ईडी ने इंदौर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं 319(2) और 318(4) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि एफआईआर संख्या 0136/2021, जो एफआईआर संख्या 041/2025 से जुड़े व्यक्तियों द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से संबंधित है, मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 419, 420, 465, 468, 471, महाराष्ट्र जुआ निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम की धाराओं 66(सी) और 66(डी) के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उक्त एफआईआर में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जांच से पता चला है कि एक तकनीकी रूप से हेरफेर किए गए तंत्र में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटें और सीमा पार धन की हेराफेरी का तरीका शामिल है। विशाल अग्निहोत्री को मुख्य संचालक के रूप में पहचाना गया है, जिनकी सहायता तरुण श्रीवास्तव ने की है। श्रीवास्तव, जो दिन—प्रतिदिन के वित्तीय संचालन और फर्जी खातों को संभालते था। श्रीनिवासन रामासामी ने फर्जी ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हेरफेरित एमटी5 सर्वरों को कॉन्फ़िगर किया था। इसके अलावा, समानांतर सट्टेबाजी नेटवर्क में धवल देवराज जैन ने भूमिगत प्लेटफॉर्म स्वजनेठववा247 का संचालन किया। धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी ने ऑफशोर इकाई पठनसस ब्वपजंस का प्रबंधन किया। निधि चंदनानी ने दुबई स्थित संरचनाओं के माध्यम से धन के प्रवाह और हेरफेर में सहायता की। ईडी की जांच में यह पुष्टि हुई है कि ग्राहकों को ट डवदमल और 8Stock Height जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से संबंध के नकली ट्रेड दिखाए गए, जबकि स्वजनेठववा247 और 11जंते जैसे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म गुमनाम खातों, एन्क्रिप्टेड संचार और नकद—आधारित निपटान का उपयोग करके गुप्त रूप से संचालित होते थे। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि हेरफेर किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और अनियमित व्हाइट लेबल एप्लिकेशन से प्राप्त 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय उत्पन्न हुई है। इसके अलावा, जांच के परिणामस्वरूप पीएओ संख्या 24/2025 के तहत 34.26 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की गई हैं। इसमें 28.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां, 3.83 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और बैंक या डीमैट खातों में 1.83 करोड़ रुपये की शेष राशि शामिल है। तलाशी के दौरान जब्त की गई प्रमुख वस्तुओं में 5.21 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 59.9 किलोग्राम चांदी की और 100 ग्राम सोने की छड़े शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सिफी के चेयरमैन राजू वेगेसना, लखनऊ-नोएडा में 'AI सिटीज' पर हुई अहम चर्चा

-आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा AI: मुख्यमंत्री

-मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से AI आधारित निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है प्रदेश सरकार : सीएम योगी

-सिफी टेक्नोलॉजी ने बीते 5 वर्षों में 12,000 करोड़ का किया है निवेश, अगले 3 वर्षों में निवेश दोगुना करने की योजना

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजू वेगेसना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट कर प्रदेश में AI आधारित डिजिटल परिवर्तन और लखनऊ व नोएडा में प्रस्तावित 'AI सिटीज़' के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से AI आधारित निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। 3 वर्षों में निवेश दोगुना करने की योजना सिफी के चेयरमैन राजू वेगेसना ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बीते 5 वर्षों में सिफी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है तथा अगले 3 वर्षों में इस निवेश को दोगुना करने की योजना है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में सिफी का AI एज डेटा सेंटर शीघ्र ही पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जबकि इसके समीप एक बड़े हाइपरस्केल AI कैंपस की भी योजना है। गूगल, मेटा और ओरेकल जैसे वैश्विक टेक दिग्गज रणनीतिक साझेदार नोएडा में सिफी उत्तर भारत के सबसे बड़े AI डेटा सेंटर कैंपस 'नोएडा—02' का संचालन कर रहा है, जिसके साथ एक अतिरिक्त AI कैंपस विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सिफी का पहला ग्रीन हाइपरस्केल डेटा सेंटर 'नोएडा—01' वर्तमान में 100 से अधिक एंटरप्राइज, सरकारी और हाइपरस्केल ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुलाकात में यह भी बताया गया कि लखनऊ और नोएडा के दोनों AI क्लस्टर्स को सिफी के राष्ट्रीय फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे हाई—स्पीड और लो—लेटेंसी AI वर्कलोड्स को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा। राजू वेगेसना ने मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी कि सिफी के डेटा सेंटर बिजनेस में गूगल, मेटा और ओरेकल जैसे वैश्विक टेक दिग्गज रणनीतिक साझेदार हैं, जो उत्तर प्रदेश की वैश्विक तकनीकी पहचान को और मजबूत करेंगे। HCL कर रही है पहले से काम बता दें कि AI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार पहले से HCL ज्मबी के साथ मिलकर

काम कर रही है। HCLSoftware के AI आधारित समाधान से जनसुनवाई (IGRS) प्रणाली में 60—70 प्रतिशत तक मैनुअल प्रयास घटा है और शिकायत निस्तारण समय लगभग 2 मिनट रह गया है, जो सुशासन का एक प्रभावी मॉडल है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जिसमें HCLTech की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नोएडा और लखनऊ में विश्वस्तरीय कैंपस तथा नोएडा स्थित ग्लोबल मुख्यालय के साथ 14 बिलियन रेवेन्यू वाली HCLTech प्रदेश के सबसे बड़े निवेशकों और निजी क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल है। यूपी में कंपनी के 50,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 75 प्रतिशत स्थानीय हैं। लखनऊ कैंपस, जो 2026 में 10 वर्ष पूर्ण करेगा, 130 से अधिक वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है और प्रस्तावित विस्तार के बाद यहां रोजगार क्षमता 18,000 से अधिक होगी। इसके साथ ही HCLFoundation की CSR पहलों से अब तक उत्तर प्रदेश में 42 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनमें 'समुदाय' और 'My Clean City' जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें और जिलों में विस्तार देने का प्रस्ताव है।

जनता की भागीदारी से ही मजबूत होती है राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यक्रम में बोलीं मुर्मू

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जिम्मेदारी की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि लोग अपने आसपास हो रही घटनाओं के केवल दर्शक नहीं बने, बल्कि सतर्क और सक्रिय भागीदार बनें। उन्होंने जन भागीदारी को लोगों के लिए केंद्रित सुरक्षा का आधार बताया। बता दें कि राष्ट्रपति ने यह बात इटेंलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के शताब्दी उपनिवेश व्याख्यान में कही, जिसका विषय था जन—केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षारू विकसित भारत के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका भी मौजूद थे। इस दौरान मुर्मू ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना और संचार

की दुनिया बदल दी है। इसके माध्यम से अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव फैल सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे सोशल मीडिया पर सच पर आधारित जानकारी साझा करें और गलत सूचनाओं से बचाव करें। जागरूकता और सफलता के मामलों का दिया उदाहरण इसके साथ ही राष्ट्रपति ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार जागरूक नागरिकों की जानकारी के कारण सुरक्षा बल गंभीर संकट टालने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पहले पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के प्रति कुछ लोग दूरी महसूस करते थे, लेकिन विकसित देशों में लोग पुलिस को भरोसेमंद और मददगार मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों का काम लोगों की सेवा करने की भावना से होना चाहिए। मुर्मू ने ड्रग्स और कट्टरपंथ जैसी समस्याओं से निपटने में जनता की भागीदारी की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां अब डिजिटल और गैर—पारंपरिक स्वरूप की हैं। डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराध से निपटने के लिए घर, संस्थान और समुदाय स्तर पर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक साइबर अपराध की जानकारी तुरंत संबंधित एजेंसियों तक पहुँचा सकते हैं और इससे भविष्य में अपराध रोकने में मदद मिल सकती है। परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों पर राष्ट्रपति ने दिया जोर राष्ट्रपति ने कहा कि सीमाओं पर तनाव, आतंकवाद, माओवादी हिंसा और साम्प्रदायिक कट्टरता जैसी परंपरागत सुरक्षा चुनौतियां अभी भी हैं। इसके अलावा भौगोलिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और व्यापार बाधाएं भी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हर समस्या का हल हमारे विशेष संदर्भ के अनुसार ढूंढना और जनता की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में भी जनता की भागीदारी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से लोगों में संघर्ष की संभावना बढ़ती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सरक्षा एजेंसियों की तारीफ की राष्ट्रपति ने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सलवाद को 31 मार्च, 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया गया है। 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब केवल 11 जिले प्रभावित हैं और सबसे अधिक प्रभावित जिले केवल तीन रह गए हैं।

BJP ने भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्ज़ा कर लिया है, राहुल गांधी ने जर्मनी से केंद्र पर नया हमला बोला

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना आरोप दोहराया है कि BJP भारत के संस्थागत ढांचे पर कंट्रोल कर रही है, जिसे उन्होंने देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर हमला बताया। जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें एक लेन—देन हुआ है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने के बजाय BJP को आर्थिक मदद दे रहे हैं। संस्थाओं पर सवाल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। विदेशी मंच से प्रहार : यह बयान उन्होंने जर्मनी के दौरे के दौरान एक संवाद कार्यक्रम में दिया। लोकतंत्र का मुद्दा : उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर वैश्विक मंच पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि

संस्थानों पर सिस्टमैटिक तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है, और कहा कि ED और CBI जैसी एजेंसियों का चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके मुताबिक, BJP के खिलाफ असल में कोई केस नहीं हैं, जबकि ज़्यादातर राजनीतिक केस सत्ताधारी पार्टी का विरोध करने वालों को टारगेट करते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले बिजनेसमैन को डराया—धमकाया जा रहा है, और तर्क दिया कि BJP राजनीतिक ताकत को मज़बूत करने के लिए सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के संसाधनों के बीच बड़े अंतर को दिखाता है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस संस्थानों पर कब्ज़े का मुकाबला करने के लिए एक विरोध का ढांचा बनाकर जवाब देगी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र पर सीधा हमला हो रहा है, और कहा कि विपक्ष मुकाबला करने के तरीके ढूंढेगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ़ एक पार्टी के तौर पर BJP के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक भारत के संस्थागत सिस्टम पर उसके कंट्रोल के खिलाफ है। INDIA ब्लॉक पर, गांधी ने माना कि गठबंधन के साथी कुछ राज्य और स्थानीय चुनावों में एक—दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने रणनीतिक मुकाबले कहा।

संपादकीय

काम का अधिकार कम न हो, उलटे इसे बढ़ाया जाना चाहिए

मनरेगा का विचार 'राइट टु वर्क' से प्रेरित था। यूएन ने काम के अधिकार को बुनियादी मानवीय हक माना था। इसे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में भी सम्मिलित किया गया है। श्रम कानून और उचित मजदूरी भी बुनियादी सिद्धांत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा में किए गए बदलावों को समझना जरूरी है। काम के अधिकार के तहत स्थानीय निकायों, विशेषकर पंचायतों, को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे स्थानीय स्तर पर चिह्नित परियोजनाओं की सूची से काम उपलब्ध कराएं और उनका क्रियान्वयन करें। मनरेगा ने इसे संस्थागत रूप दिया था। अनेक वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण, जीपीएस टैगिंग और मजदूरी के सीधे बैंक खातों में भुगतान से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हुई। वहीं राज्यों ने मनरेगा को अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के साथ जोड़ा, जिससे टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। लेकिन नई योजना के तहत किए गए बदलाव इस मॉडल से हटने का संकेत देते हैं। चयनित क्षेत्रों और सीमित कार्यों को एक केंद्रीकृत ढांचे में सीमित कर देने से स्थानीय जरूरतों की पहचान कमजोर होगी। खेती के मौसम के दौरान वाले कार्यों को बंद करने से खेत–मजदूर की मोलभाव की क्षमता कमजोर होगी। जबकि पुरानी योजना के तहत मनरेगा ने कृषि मजदूरी को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। नई व्यवस्था में चिंता का विषय केवल यही नहीं है कि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40: कर दी गई है– जो पहले सामग्री की लागत का केवल 10: थी। चिंता का विषय यह भी है कि इससे राज्यों के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी के बाद कर–संग्रह मुख्यतया केंद्र के हाथ में चला गया है (ईंधन पर वैट और शराब पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर)। सीमित संसाधनों वाले राज्य 40: हिस्सेदारी को वहन करने में असमर्थ रहेंगे, जिसका नतीजा मजदूरी के भुगतान में देरी या काम न मिलने के रूप में सामने आ सकता है। एक और समस्या उस शर्त से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि काम 'फंड की उपलब्धता' के अनुसार दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि काम पर सीमा तय कर दी गई है, जो 'काम के अधिकार' की मूल भावना के विपरीत है। अब काम तभी मिलेगा, जब पैसा होगा। नई व्यवस्था में जिन क्षेत्रों को कार्य के लिए चिह्नित किया गया है, वे भी श्रम की तुलना में अधिक सामग्री–आधारित हैं। उदाहरण के लिए जल परियोजनाओं में अधिकतम खर्च पाइप और टैंक निर्माण पर होता है, यही स्थिति टॉयलेट्स के निर्माण में भी है। इससे श्रम आधारित रोजगार सृजन की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। इसके विपरीत, पहले की व्यवस्था के तहत सड़क निर्माण में मिट्टी के काम, कृषि भूमि में कार्य, कुओं का निर्माण जैसे श्रम–प्रधान कार्य संभव हो पाते थे, जिससे अधिक रोजगार सृजित होते थे। जरूरत इस बात की है कि नई योजना के स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए और कार्यों की उपलब्धता पूरे साल सुनिश्चित की जाए। 'काम के अधिकार' की मूल भावना यह है कि परियोजनाओं की उपलब्ध सूची से, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर, मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए और परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो। निस्संदेह, इस व्यवस्था में समय–समय पर सुधार की आवश्यकता रही है और आगे भी रहेगी, विशेष रूप से समय पर धन का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए। कार्य क्षेत्रों को सीमित करने की अवधारणा केवल पिछड़े और आदिवासी जिलों तक ही उचित हो सकती है। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार विकेंद्रीकृत होना चाहिए। कई बार आपदा की स्थिति में बड़े पैमाने पर काम लेना अनिवार्य हो जाता है– जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। तब प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा जीवनरेखा साबित हुई थी। मनरेगा पहली ऐसी योजना थी, जिसने मजबूत घरेलू डेटा आधार पर डीबीटी को लागू किया और वित्तीय–समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की। शून्य–बैलेंस खाते खोले गए, जो बाद में बचत खातों में बदले और जमा तथा अन्य बचत लाभों को प्रोत्साहित किया। मनरेगा किसी भी तरह के खाद्यान्न वितरण की तुलना में कहीं अधिक समावेशी योजना साबित हुई थी और मजदूरी के माध्यम से भुगतान ने लाभार्थियों की गरिमा भी बनाए रखी थी। मनरेगा किसी भी तरह के खाद्यान्न वितरण की तुलना में कहीं अधिक समावेशी योजना साबित हुई थी और मजदूरी के माध्यम से भुगतान ने लाभार्थियों की गरिमा भी बनाए रखी थी। इसकी मूल भावना यथावत रहनी चाहिए।

2026 के लिए क्या कहती हैं भविष्यवाणियां

–कल्याणी शंकर

भविष्यवाणियों में मशहूर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां शामिल हैं, जिनकी भविष्यवाणियों की अलग–अलग तरह से व्याख्या की गई है। भविष्यवाणी की गई घटनाओं में दो विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी और अमरीका में 9/11 के आतंकवादी हमले शामिल हैं, ये सभी भविष्यवाणियां 1555 में लिखी गई थीं। उनके लेखों की अस्पष्ट भाषा कई तरह की व्याख्याओं को जन्म देती है और इतिहासकार अक्सर उनकी भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता पर बहस करते हैं। 2026 के लिए नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां महत्वपूर्ण वैश्विक अशांति का संकेत देती हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष बढ़ेंगे, जिससे एक बड़ा युद्ध हो सकता है, जो लगभग 7 महीने तक चल सकता है। वह स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में खून–खराबे की भी चेतावनी देते हैं। कुछ व्याख्याओं का कहना है कि एक शक्तिशाली 'प्रकाश का आदमी' दिखाई देगा, साथ ही और भी जलवायु आपदाएं और तकनीकी बदलाव होंगे। बाबा वेंगा, एक प्रतिष्ठित बल्गारियाई भविष्यवक्ता, ने भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और गंभीर जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण आपदाओं के बारे में अपनी भविष्यवाणियों के लिए पहचान हासिल की। ये पर्यावरणीय बदलाव बाढ़, सुनामी और अन्य चरम घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जो संभावित रूप से दुनिया भर के क्षेत्रों और सैक्टरों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें कृषि, बुनियादी ढांचा और आपदा तैयारी शामिल है। हालांकि इन विचारों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है लेकिन उनके संभावित प्रभावों पर विचार करने से हमें भविष्य के जोखिमों को समझने में मदद मिलती है। अगले साल, विभिन्न देशों में 10 चुनाव होने वाले हैं। वे हैं– इथियोपिया, अमरीका, म्यांमार, दक्षिण सूडान, गाम्बिया, सूडान, रूस, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड। दुनिया भर में हर 100 लोगों में से लगभग 7 से 8 लोग इन घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जो दिखाता है कि कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। इन विचारों में एक मजबूत वैज्ञानिक आधार की कमी है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि ये अवधारणाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। भारत भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। तमिलनाडु में, अन्नाद्रमुक गठबंधन द्रमुक को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन द्रमुक मजबूत और एकजुट बनी हुई है। केरल में, भले ही भाजपा फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य लैफ्ट डैमोक्रेटिक फ्रंट (एल.डी.एफ.) और यूनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट (यू.डी.एफ.) के बीच बंटा हुआ है। असम में, जहां अभी भाजपा सत्ता में है, आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी राज्य में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मुकाबला करेंगी। भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, फिर भी इसके मजबूत बने रहने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों को भरोसा मिलता है। आर्ध्टफिशियल इंटैलीजैंस (ए.आई.) में निवेश के कारण विकास दर में सुधार होना चाहिए। अलग–अलग मौद्रिक नीतियों और ज्यादा सार्वजनिक कर्ज पर भी नजर रखनी जरूरी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस और चीन संसाधनों के लिए मुकाबला कर रहे हैं, जिससे संभावित रूप से संघर्ष हो सकते हैं। यह नोस्ट्राडेमस की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में चेतावनियों से मेल खाता है। बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी थी। 2026 तक, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। यह मंदी शायद व्यापार तनाव और जनसांख्यिकीय बदलावों, खासकर विकसित देशों में बढ़ती उम्र की आबादी के कारण होगी। अमरीका में 2.2 प्रतिशत की दर से विकास होने का अनुमान है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा चुनौतियों को दर्शाता है। गोल्डमैन साक्स रिसर्च का अनुमान है कि 2026 तक, ज्यादातर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पहले की तुलना में तेजी से विकास होगा। अमरीका के लिए दृष्टिकोण मजबूत है, जो हाल के टैक्स बदलावों, बेहतर वित्तीय स्थितियों और कम टैरिफ के कारण है। भारत में, मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है, जिससे सामर्थ्य के बारे में महत्वपूण चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर चल रहे व्यापार तनाव और नीतिगत बदलावों के बीच। हालांकि, ऑटिफिशियल इंटैलीजैंस में बढ़े हुए निवेश के साथ–साथ कम टैरिफ से उत्पादकता बढने और महत्वपूर्ण आध्र्थक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2026 और उसके बाद के लिए भारत का आर्थिक दृष्टिकोण वैश्विक टैरिफ झटकों और घरेलू नीतियों की प्रभावशीलता से प्रभावित होगा। 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए, सरकार को घरेलू विकास को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकघ्षत करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने के बीच संतुलन बनाना होगा। भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण वैश्विक टैरिफ झटकों और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए घरेलू बफर्स और नीतिगत उपायों की क्षमता के बीच तालमेल को दर्शाता रहेगा, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2026 में, भारत की विदेश नीति 'पड़ोसी पहले' और 'एक्ट ईस्ट' पहलों पर जोर देते हुए मल्टी–अलाइनमैंट रणनीति को लागू करना जारी रखेगी। देश क्वाड (क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग) के जरिए अमरीका और यूरोप, खासकर जर्मनी के साथ रक्षा और आध्र्थक सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक सांझेदारी को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा, भारत 2026 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता का इस्तेमाल ग्लोबल साऊथ के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए करना चाहता है, साथ ही प्रमुख शक्तियों, खासकर अमरीका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता को भी संबोधित करना चाहता है। यह नीतिगत ढांचा बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच रणनीतिक स्वायत्तता और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए कनैक्टिविटी, डिजिटल कूटनीति और जलवायु परिवर्तन में पहलों को भी प्राथमिकता देता है। संक्षेप में, भारत की 2026 की विदेश नीति मुखर कूटनीति, मजबूत सांझेदारी बनाने, ग्लोबल साऊथ का नेतृत्व करने और एक जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करने के बारे में है, जो व्यावहारिकता और 'भारत के वैश्विक पदचिन्ह' पर स्पष्ट फोकस द्वारा चिन्हित है। कुल मिलाकर, 2026 में भारत के लिए मजबूत घरेलू मांग, सरकारी नीतिगत समर्थन और बढ़ते डिजिटल और हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के कारण मजबूत आध्र्थक विकास और बढ़ती वैश्विक प्रमुखता का वर्ष होने का अनुमान है। हालांकि, इस वर्ष कुछ चुनौतियां भी आने की उम्मीद है, जिनमें वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और रोजगार बाजार में थोड़ी मंदी शामिल है।

देश में ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज

बिहार चुनाव जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प.बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। बीते दो दिनों में उनकी दो सभाएं प.बंगाल और असम में हुईं। प.बंगाल के नादिया जिले में उनका हेलीकॉप्टर धुंध की वजह से न उतर सका तो उन्होंने कोलकाता से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नादिया में उनके खिलाफ पोस्टर और बैनर लगे थे, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या श्री मोदी विरोध का सामना करने से डर गए और इसलिए धुंध को लौटने का कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पंजाब चुनाव के वक्त वे किसानों के विरोध की वजह से बीच रास्ते से लौट आए थे और तब उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। लोकतांत्रिक देश में जनता के विरोध को जान पर खतरे की तरह दिखाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकार सुहाते नहीं हैं। खैर, ठंड का मौसम बीतेगा और धुंध खत्म होगी, तब तो नरेन्द्र मोदी को बंगाल में प्रचार के लिए जाना ही होगा, तब अगर विरोध होता है, तो कितनी बार वे लौटेंगे, ये देखना होगा।प.बंगाल में नरेन्द्र मोदी असम गए और वहां उन्होंने इतिहास की गलत बयानी कर पं.नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस कोशिश में श्री मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना दिया है कि आखिर कब तक वे इतिहास को तोड़–मरोड़ कर पेश करेंगे। दरअसल श्री मोदी ने 20 दिसंबर को गुवाहाटी में आरोप लगाया कि श्कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी, जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ताकतें मिलकर भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रही थीं, उस समय असम को भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना थी। कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। तब बोरदोलोई जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान मिटाने की इस कोशिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर अलग–अलग प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। उत्तर–पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और भारत के शेष मध्य भागों के लिए समूह ए, बी और सी नामक तीन समूहों का प्रस्ताव रखा गया था। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत (जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूपी) थे, समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत (पंजाब, सिंध, उत्तर–पश्चिमी सीमांत प्रांत) थे और समूह सी में बंगाल और असम, जिसमें बंगाल मुस्लिम बहुल था, जबकि असम हिंदू बहुल। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पूरा समूह सी पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही कांग्रेस ये चाहती थी कि असम को बंगाल के साथ मिलाया जाए। 29 दिसंबर 1946 के श्हरिजनश् अखबार में श्गांधीजी की असम को सलाहश् शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नेहरू भी असम को पाकिस्तान या बंगाल के साथ मिलाने के खिलाफ थे। 22 जुलाई 1946 को गोपीनाथ बोरदोलोई को पत्र में नेहरूजी ने लिखा, श्समूह के खिलाफ फैसला करना सही और उचित था।श् इसके बाद 23 सितंबर 1946 को लिखा, श्किसी भी हालत में हम असम जैसे प्रांत को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने पर सहमत नहीं होंगे।श् अप्रैल 1946 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पं. नेहरू ने कहा, श्उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया... असम भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है।श् कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद अंग्रेजों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने की योजना को रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की स्पष्ट अस्वीकृति और असहमति माना गया। ये सारी बातें सौ साल पुरानी भी नहीं हैं, तब के अखबारों की कतरनों में देखा जा सकता है कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस पार्टी और गोपीनाथ बोरदोलोई सबके विचार इस मुद्दे पर एक जैसे थे। लेकिन नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि बोरदोलोई ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम बचाया।दरअसल असम में अब भाजपा के खिलाफ एंटीइनकमबेंसी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में वहां लगातार जमीन पर सक्रिय है। इसलिए भाजपा अब वहां झूठा इतिहास बताकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है, जिसमें नरेन्द्र मोदी का पहला ही दांव बेकार गया है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी भाजपा शुरु से उठाती रही है और हिमंता बिस्वासरमा लगातार सांप्रदायिक विभेद बढ़ाने वाले फैसले ले रहे हैं, इनका लाभ भाजपा को मिलेगा या नहीं देखना होगा।

जानलेवा आबोहवा

देश–दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम–होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक्यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे। हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड–ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो–बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अधिक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल–रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव–सफाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है।

राशिफल

मेष :– कोई छोटी बात भी परिवार कें तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता नये उत्साह का संचार करेगी। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिब्यक्ति से संबंध मधुर बनेंगे।

बृषभ :– हर घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व बुद्धिजीवियो से विचार–विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को मन पर हावी न होने दें। नये व्यावसायिक यात्राएं करनी होंगी।

मिथुन :– निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुन्दर छबि बनावें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओ की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा।

कर्क :– भविष्य के प्रति मन में चिंताएं उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा–बड़ा समझने के बजाए अपने कर्त्तव्यों का ठीक डंग से निर्वहन् करें। वर्तमान कार्य से मन में असन्तुष्टि उत्पन्न होगी। आलस्य का त्याग करें।

सिंह :– पारिवारिक दायित्वों की चिंता उत्पन्न होगी। स्वास्य के प्रति लापरवाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्य के प्रति ध्यान देवें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ब्यवस्था के लिए मन प्रयत्नशील होगा।

कन्या :– छोटी–छोटी पारिवारिक बातों को बाहरी लोगों से न कहें। भावना से उद्वेलित मन सगे–संबंधियों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाएं याद आएंगी।

तुला :– वक्त के साथ समझौता कर चलने की चेष्ठा करें। अपने कार्यक्षेत्र को ही अपनी पूजा समझे और अपने को उसी दिशा की ओर केंद्रित करें। रोजगार में अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ उठाएंगे।

वृश्चिक :– जीवन में सही लक्ष्य व सुदृढ़ता को सुनिश्चित करें तभी जीवन में सही प्रगति कर सकते हैं। किसी पुराने संबंधी से बिशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होने के आसार हैं।

धनुः– किसी भी प्रयास में आर्थिक अभाव अवरोधक होगा। साहस व बुद्धिमत्ता से पुरानी समस्याओं पर बिजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे।

मकर :– बुद्धिमत्ता व परिश्रम का मिला–जुला संजोग का भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सफलताएं आंतरिक क्षमताओं का एहसास कराएंगी। घर में खुशहाल स्थिति प्रसन्न रखेगी।

कुंभ :– शासन–सत्ता में ब्यस्तता बढ़ेगी। मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु चिंतित होगा। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा।

मीन :– महत्वाकांक्षी अभिलाषाएं मन में असन्तुष्टि पैदा करेंगी। तामसिक विचारों को मन से दूर रखें। विपरीतलिंगी संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में ब्यय अपेक्षित है।

एक्सप्रेस वे पर लोगों को चलना सिखाना होगा

–अशोक मधुप

विकास की रफ़्तार तभी सुखद है जब वह सुरक्षित हो। भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, विशेषकर सड़क तंत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, वे अभूतपूर्व हैं। जहाँ पहले दो शहरों के बीच का सफर घंटों और दिनों में तय होता था, आज वह समय काफी कम हो गया है। लेकिन इस भौतिक प्रगति के बीच एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। क्या हम इन आधुनिक सड़कों पर चलने के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार हैं? अब समय आ गया है कि हम ईंट और डामर की सड़कों से आगे बढ़कर श्मानव व्यवहारश् में सुधार पर निवेश करें। याद रखिए, एक्सप्रेसवे केवल मंजिल तक जल्दी पहुँचने के लिए नहीं हैं, बल्कि सुरक्षित पहुँचने के लिए हैं। यदि हम गति के साथ गरिमा और अनुशासन नहीं अपना सकते, तो ये चमचमाती सड़कें हमारे लिए वरदान के बजाय अभिशाप सिद्ध होंगी। अब जरूरत है किष्हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने से पहले लोगों को उन पर चलना सिखाना चाहिएष्कृ यह केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि समय की मांग है। केवल कंक्रीट के जाल बिछाने से राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, बल्कि उन सड़कों पर सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना भी सरकार और नागरिक दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत में सड़क निर्माण की गति पिछले दस वर्षों (2014–2024) में सांख्यिकीय और भौगोलिक दोनों दृष्टि से ऐतिहासिक रही है। 2014 के आसपास देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 91,287 किलोमीटर थी, जो 2024 तक बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। 2014–15 में सड़क निर्माण की दर लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में बढ़कर औसतन 28 से 37 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुँच चुकी है। भारत ने श्भारतमाला परियोजनाश् के तहत विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे गलियारे भारत की नई पहचान बन चुके हैं। अटल टनल और चेनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार इसी दशक की देन हैं, जिन्होंने दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा है। इतना सब हुआ। सड़कों की चौड़ाई तो बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हमारी लापरवाही की कीमत बहुत भारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में हुई 4,49,002 दुर्घटनाओं 1,51,113मौत हुईं। 2020 में हुई 3,66,138 दुर्घटनाओं में 1,31,714 व्यक्ति मरे। 2021 में हुए 4,12,432 एक्सीडेंट में 1,53,972 व्यक्ति मौत के मुंह में समा गए। 2022 में हुई 4,61,312 दुर्घटनाओं मे 1,68,491 जान गईं। 2023 हुई 4,80,000+ (अनुमानित) में 1,70,000 व्यक्ति मौत के शिकार हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घायलों की संख्या तो मरने वालों से काफी ज्यादा होनी चाहिए। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 19 लोग मरे। 100 से ज्यादा घायल हुए। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लगभग 70 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं श्ओवरस्पीडिंगश् यानी अत्यधिक गति के कारण होती हैं। एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की गंभीरता सामान्य सड़कों से कहीं अधिक होती है क्योंकि यहाँ वाहनों की गति बहुत तेज़ होती है। एक्सप्रेसवे सामान्य सड़कें नहीं हैं। यहाँ ड्राइविंग के अपने नियम हैं, जिन्हें भारतीय चालकों को सीखना होगा। इन पर चलते समय लेन का अनुशासन का पालन करना होगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग भारी वाहन सबसे दाईं ओर चलाते हैं, जबकि वह लेन केवल ओवरटेकिंग के लिए होती है। तेज़ रफ़्तार वाली सड़कों पर गलत लेन में वाहन चलाना आत्महत्या के समान है। एक्सप्रेसवे पर केवल अधिकतम गति ही नहीं, बल्कि न्यूनतम गति का पालन भी जरूरी है। धीमी गति से चल रहे वाहन तेज़ रफ्तार वाहनों के लिए अवरोध बन जाते हैं, जिससे टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। एक्सप्रेसवे की सीमेंट वाली सड़कों पर टायर बहुत जल्दी गर्म होते हैं। यदि टायर पुराने या घिसे हुए हैं, तो वे फट सकते हैं। लोगों को यह सिखाना जरूरी है कि लंबी यात्रा से पहले अपने वाहनों की तकनीकी जांच कैसे करें। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए बने रास्तों (रैम्प) का सही उपयोग करना अधिकांश लोगों को नहीं आता। अचानक मुख्य मार्ग पर वाहन मोड़ देना घातक होता है। वाहनों की संख्या और लाइसेंस धारकों के बीच का यह अंतर यह दर्शाता है कि हमारी सड़कों पर श्अकुशलश् चालकों की फौज मौजूद है। एक्सप्रसवे जैसी तेज़ रफ़्तार वाली सड़कों पर यह स्थिति और भी घातक हो जाती है। एक आदर्श स्थिति में, सड़क पर चल रहे हर वाहन के अनुरूप कम से कम एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। हालांकि, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार, देश में कुल ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या लगभग 21 से 23 करोड़ के बीच है। यदि हम 35 करोड़ पंजीकृत वाहनों की तुलना 23 करोड़ लाइसेंसों से करें, तो स्पष्ट होता है कि वाहनों और चालकों के बीच 12 करोड़ का भारी अंतर है। विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (त्ज्व्) और पुलिस द्वारा चलाए गए जांच अभियानों के अनुसार, बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 25से 30 प्रतिशत लोग बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन चला रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हादसों में जान गंवाने वाले या दोषी पाए जाने वाले चालकों में से लगभग 65 प्रतिशत युवाओं के पास वैध लाइसेंस नहीं होता। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत और भी अधिक है, जहाँ लगभग 40 प्रतिशत दोपहिया चालक बिना लाइसेंस के गाड़ी दौड़ा रहे हैं। एक पुरानी रिपोर्ट (सेव लाइफ फाउंडेशन) यह भी बताती है कि जिनके पास लाइसेंस है, उनमें से भी 10 में से छह लोगों ने बिना किसी व्यावहारिक ड्राइविंग टेस्ट के इसे प्राप्त किया है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है। इसलिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने पर केवल जुर्माना नहीं, बल्कि वाहन को लंबे समय के लिए ज़ब्त करना होगा। नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने पर अभिभावकों को जेल की सजा का प्रावधान में कड़ाई जरूरी है। डिजिटल तकनीक का उपयोग कर हर मोड़ पर बिना लाइसेंस वाले पर कार्रवाई अमल में लानी होगी। इन एक्सप्रेसवे पर चलना सिखाने के लिए सिर्फ शिक्षा पर्याप्त नहीं है; अनुशासन के लिए कानून का भय भी आवश्यक है। गलत वाहन चलाने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और उल्टी दिशा (रॉन्ग साइड) में चलने वालों पर इतनी सख्ती होनी चाहिए कि वे दोबारा नियम तोड़ने की हिम्मत न करें। बार–बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए। हर कुछ किलोमीटर पर कैमरे और रडार होने चाहिए जो नियम तोड़ते ही चालान सीधे चालक के पते पर भेजें। नियम पन मानने वालों पर जुर्माना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दंडात्मक होना चाहिए ताकि वह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाले। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक किलोमीटर पर कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह तो पूरे देश के महत्वपूर्ण मार्ग पर करना होगा, तभी दुर्घटनाएं रूकेंगी। सड़क सुरक्षा को केवल पुलिस का विषय न मानकर इसे शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा। विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही सड़क के संकेतों, लेन अनुशासन और जीवन के मूल्य के बारे में सिखाया जाना चाहिए। जब तक सुरक्षा की भावना हमारे संस्कार में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक सड़कें केवल मृत्यु के गलियारे बनी रहेंगी।

किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया पुष्पार्चन, 'किसान सम्मान दिवस' में भी हुए शामिल

सीएम ने किसानों को दी ट्रैक्टर की चाबी, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लॉट आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर किया शुभारंभ

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी मेहनत को प्रणाम किया। सीएम ने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरे की चमक का जिक्र किया। बोले कि कोई किसान अपनी मां तो कोई पत्नी को ट्रैक्टर में बिठाकर ले जा रहा है। यही किसान की ताकत होती है, सर्दी, गर्मी की परवाह किए बिना जब वह पसीना बहाता है और सर्दी को अपनी अस्थियों में समाहित कर ऊर्जा का प्रवाह धरती मां के साथ करता है तो खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर विधान भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सीएम ने 'किसान सम्मान दिवस' पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लॉट आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया।

2014 में पहली बार किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। धरती हमारी मां और हम सभी इसके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र का दायित्व है कि जब मां बीमार या संकट में हो तो पुत्र उसे संकट से उबारने में योगदान देता है। पहली बार स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पीएम मोदी ने 2014 में धरती मां की सेहत के बारे में हर किसी को जागरूक किया। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा, फिर एक–एक करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया।

अब किसानों को मिलता है शासन की हर योजना का लाभ

सीएम योगी ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को 'भारत रत्न' देकर किसानों का मान बढ़ाया। लघु व सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम लागू किया। पहले किसान शासन की किसी भी योजना का अंग नहीं था, लेकिन आज किसान को शासन की हर योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज बिचौलिया किसानों की फसल का दाम नहीं तय करता। यदि किसान को बाजार में फसल का अच्छा दाम मिला तो ठीक वरना सरकार उसे खरीदेगी। यूपी के अंदर धान, गेहूं, चना, सरसो, बाजरा, मक्का आदि फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और लागत कम हुई है। यही किसानों की समृद्धि का आधार है।

देश, गांव व किसान के हितैषी थे चौधरी चरण सिंह

सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य का जिक्र किया। वे हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। वे कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारत की समृद्धि का मार्ग देश के खेत व खलिहान से होकर गुजरता है। जागरूक जनशक्ति ही सफल लोकतंत्र का आधार है। यूपी सरकार में उन्हें जब मौका मिला तो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद करने के लिए मंडी अधिनियम पारित कराया। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु–सीमांत किसानों के साढ़े तीन एकड़ तक के भूखंड को भूराजस्व के भुगतान में छूट भी दिलाई। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरूआत भी की। कृषि व ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

यूपी में किसान समृद्धि की तरफ अग्रसर हुआ

सीएम योगी ने कहा कि 1996 से 2017 (21–22 वर्ष) में किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, उससे लगभग 75 हजार करोड़ रुपये अधिक धनराशि 8 वर्ष में किसानों के खाते में डाली है। अभी हाल में ही गन्ना मूल्य का दाम बढ़ाया है। पेराई सत्र 2025–26 में अगेती गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। सीएम ने कहा कि यूपी में किसान समृद्धि की तरफ अग्रसर हुआ है। किसानों ने नई तकनीक और अच्छी क्वालिटी के बीज पर ध्यान दिया तो कम लागत में अच्छा उत्पादन कर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

हमारे तो मंत्री भी किसान हैं

सीएम योगी ने कहा कि 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। यूपी में इनकी संख्या अब 89 हो गई है। 9 क्लाइमेटिक जोन में इतने कृषि विज्ञान केंद्र किसी राज्य में नहीं हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारे मंत्री (सूर्य प्रताप शाही, चौधरी लक्ष्मी नारायण, बलदेव सिंह औलख) किसान हैं और संजय निषाद मत्स्य उत्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं।

सीएम ने सरकार के कार्यों को भी गिनाया

सीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में आधुनिक तकनीक पर आधारित सीड पार्क बन रहा है। उत्तम क्वालिटी का बीज किसानों को समय पर मिल जाए और वह समय पर खेती करे तो 30 फीसदी उत्पादन बढ़ सकता है। बाराबंकी में टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब के लिए 31 एकड़ चिह्नित किया है, जो टिश्यू कल्चर (गन्ना, केले, आलू आदि फसलों) के क्षेत्र में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। सीएम योगी ने पद्मश्री रामसरन वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों ने जमीन के नीचे आलू व ऊपर टमाटर पैदा किया है। हर किसान को प्रशिक्षित भी करते हैं। इस बार किसान पाठशाला उनके गांव दौलतपुर में लगाई थी।

किसान तब समृद्ध होगा, जब उसे तकनीक और समय पर खाद–बीज देंगे

सीएम योगी ने कहा कि शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच में गन्ना किसानों ने एक–एक हजार कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम ने कृषि व गन्ना विभाग से कहा कि हर किसानों को वहां ले जाकर तकनीक से अवगत कराया जाए। किसान तब समृद्ध होगा, जब उसे तकनीक, समय पर खाद–बीज देंगे। सीएम ने कहा कि कैंसर, किडनी–लीवर और बीमारियों से बचाना है तो उसका एकमात्र साधन प्राकृतिक खेती है।

सीएम ने किसान हित के कार्यों को गिनाया, बोले– अब योजनाओं की स्पीड सुस्त नहीं है

सीएम ने किसानों के हित में किए गए कार्य को गिनाया। बोले कि 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े किसानों का ऋण माफ कर दिया है। हर वर्ष सरकार 3600 करोड़ रुपये पावर कॉरपोरेशन को देती हैं। सहकारिता के माध्यम से संचालित एलडीबी के द्वारा किसानों को साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, अब यह छह फीसदी पर मिलेगा। किसान के हित में सरकार सब कुछ करेगी। अब योजनाओं की स्पीड सुस्त नहीं है। अब किसानों को सुरक्षा की चिंता नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। चौधरी चरण सिंह की सोच के अनुरूप डबल इंजन सरकार किसानों के हितों के लिए सदा कार्य करेगी। किसान सम्मान दिवस में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, धर्मपाल सिंह, डॉ. संजय निषाद, अनिल कुमार, दिनेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता समेत भाजपा व रालोद के कई विधायक भी मौजूद रहे।

संक्षिप्त

यूपी विधानसभा सत्र, अध्यक्ष सतीश महाना बोले- सदन में आरोप लगाने से पहले सभी सदस्य दें शपथ पत्र

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों से कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले उनके समक्ष शपथ पत्र भेजें। समाजवादी पार्टी (सपा) के एक सदस्य ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों से संबंधित प्रश्न के लिखित उत्तर से असंतोष जाहिर करते हुए सरकार पर गलत सूचना देने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल समाप्त हो जाने की वजह से पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलने पर सपा के वरिष्ठ

सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार ने उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। उनके इस आरोप पर प्रतिरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने सही जवाब दिया है। इस बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह परंपरा बन गई है कि जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सीधा जवाब न देकर पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं। नियम है कि किसी के ऊपर आरोप लगाने पर सबूत होने चाहिए। यह परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग उसी समय विरोध करेंगे। पांडेय ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह द्वारा शिक्षा से जुड़े एक प्रश्ध्न पर दिये गये जवाब को लेकर आपत्ति की थी। खन्ना ने कहा कि मंत्री ने किसी दल का नाम नहीं लिया और पिछली सरकारों की बात की है। इस वाद–विवाद के बीच व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, मैं सभी सदस्यों से कहूंगा, आरोप लगाने से पहले शपथ पत्र मेरे टेबल पर भेज दें। यह सदन के सभी 403 सदस्यों पर लागू होगा। यह प्रश्न पूछने वाले और सरकार के ऊपर भी लागू होगा। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछे तो या तो उसे प्रमाणित करेगा, तभी पूछा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पांडेय ने इस पर आपत्ति की तो महाना ने कहा कि ''अब आप पलट गए''। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को तीसरे दिन हाल में दिवंगत पांच पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूर्व विधायक पूर्णमासी पंकज (भदोही), याद अली (प्रतापगढ़) सैयद अली अशरफी (पीलीभीत), राम सिंह एडवोकेट (मैनपुरी) और लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (चित्रकूट) के हाल में निधन होने की जानकारी सदन को दी और उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला।

प्रयागराज में किया गया 06 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारम्भ

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण में आयेगी कमी-दयाशंकर सिंह

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। जनपद प्रयागराज में स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत आज लीडर रोड डिपो कार्यशाला प्रयागराज में आरजी मोविलिटी द्वारा 06 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारम्भ किया गया। उक्त बसों का संचालन प्रयागराज से वाराणसी, अयोध्या व कानपुर मार्गों पर किया जायेगा।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने मा0 मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को प्रदूषण रहित आरामदायक एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में परिवहन निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसका सीधा लाभ पर्यावरण को होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसे शून्य उत्सर्जन तकनीकी पर आधारित है, जिससे वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रूदषण में उल्लेखनीय कमी आयेगी। साथ ही डीजल ईंधन पर निर्भरता घटेगी और

ईंधन लागत में बचत होगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। यह पहल प्रदेश सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीति, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रयागराज, अयोध्या एवं वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन नगरों के बीच आधुनिक एवं हरित परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महापौर प्रयागराज गणेश केसरवानी, डीजी आरजी मोविलिटी सेरगई कोलिकोव, आरएम प्रयागराज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यूपी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की नई पहल, सड़क सुरक्षा मित्र और राहवीर योजनाओं का विस्तार

सीएम के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा मित्र और राहवीर योजनाएं प्रदेश में सड़क सुरक्षा को दे रही नया आयाम

सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 28 जनपदों के लिए 14 लाख का बजट आवंटित

गोल्डन आवर में दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर को मिलता है 25,000 का इनाम, यूपी में 5 राहवीर का चयन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम और राहवीर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम के निर्देश के बाद इन दोनों योजनाओं के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में सक्रियता बढ़ाई गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं में सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाना और दुर्घटना पीड़ितों की त्वरित सहायता और चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करना है। जिससे एक ओर तो रोड एक्सीडेंट के मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सके, दूसरी ओर दुर्घटना की स्थिति में मौत की संख्या को कम करना है। राज्य सरकार ने इनकी निगरानी के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा को जन–आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। प्रदेश के 28 जनपदों में सक्रिय है सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम केंद्र सरकार का सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम वर्तमान में प्रदेश के 28 जनपदों में सक्रिय है, यह योजना युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियानों में सक्रिय भागीदार बनाने पर केंद्रित है। कार्यक्रम के तहत यूपी में अब तक 423 युवा स्वयंसेवकों ने माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके तहत राज्य लोक सेवा फाउंडेशन ने गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। जिसमें स्वयंसेवकों को सड़क सुरक्षा नियमों, दुर्घटना प्रबंधन और जागरूकता अभियानों की ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम के लिए 14 लाख रुपये का बजट अनुमोदित किया गया है, जिसमें सभी 28 जनपदों के लिए 50,000 रुपये का प्रावधान है। यह धनराशि सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी। सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के सफल संचालन से प्रदेश में न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि युवाओं में जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का भी विकास होगा। बस्ती, कौशांबी, सीतापुर, अलीगढ़ और कासगंज से चुने जा चुके हैं 5 राहवीर राहवीर योजना सड़क दुर्घटनाओं के गोल्डन आवर, दुर्घटना के पहले एक घंटे में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर फोकस करती है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना आम नागरिकों को प्रेरित करती है कि वे दुर्घटना पीड़ितों की तत्काल सहायता प्रदान करें। योजना के तहत, जो राहवीर पीड़ित को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाता है, उसे 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य रोड एक्सीडेंट के मामलों में मौत की संख्या में कमी लाना है। प्रत्येक जनपद में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को इस योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। यूपी में इस योजना के तहत अब तक पांच शराहवीरश चुने जा चुके हैं जो जनपद बस्ती, कौशांबी, सीतापुर, अलीगढ़ और कासगंज से संबंधित हैं। ये योजनाएं उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा हाईवे और विशाल रोड नेटवर्क वाले राज्य में सड़क सुरक्षा को नया आयाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य परिवहन विभाग ने आगामी महीनों में और अधिक प्रशिक्षण शिविरों की योजना तैयार की है। साथ ही नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से अपील है कि वे इन योजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करें और प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित बनाने में योगदान दें।

पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का विशाल प्रदर्शन और सभा

लंबे संघर्ष और हड़ताल के लिए तैयार रहें बैंककर्मी - डी के सिंह, महामंत्री

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मियों ने केंद्र सरकार द्वारा ष्पांच दिवसीय बैंकिंग लागू न करने के विरोध में हजरतगंज स्थित इंडियन बैंक की शाखा के सामने जोरदार प्रदर्शन और सभा की। फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस मुद्दे पर फोरम ने अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। कामरेड डी के सिंह (महामंत्री, एनसीबीई) ने कहा कि बैंककर्मियों पर बढ़ते हुए तनाव और दबाव के चलते ष्पांच दिवसीय बैंकिंगष शीघ्र लागू होनी चाहिए और ऐसा न होने पर बैंक कर्मी लंबे संघर्ष और हड़ताल के लिए तैयार है। काम. वाई के अरोड़ा, आर एन शुक्ला, मनमोहन दास, एस के संगतानी, संदीप सिंह, वी के माथुर, विशाखा वर्मा आदि बैंक नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आर.बी.आई., एल.आई.सी. व जनरल इंश्योरेंस आदि में पांच दिवसीय कार्य दिवस प्रणाली लागू है तो फिर बैंककर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सभा को विभिन्न घटक दलों के बैंक नेताओं काम. एस डी मिश्रा, शकील अहमद, लक्ष्मण सिंह, बी डी पांडे, विभाकर कुशवाहा, यू पी दुबे, मनीष कांत, ललित श्रीवास्तव आदि ने भी संबोधित किया. अनिल तिवारी (मीडिया प्रभारी) ने बताया कि आगामी 30 दिसंबर को केनरा बैंक (आंचलिक कार्यालय, गोमती नगर), बैंक ऑफ़ इंडिया (चौक शाखा), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (कपूरथला शाखा) तथा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (हजरतगंज शाखा) पर बैंककर्मियों द्वारा संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा.

पारिवारिक दलों का गठबंधन है अखिलेश का पीडीए : पंकज चौधरी

संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर

निशाना साधते हुए कहा है कि उनका पीडीए का मंत्र परिवारवाद गठबंधन से ज्यादा कुछ नहीं है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देश की राजनीति का केंद्र बताते हुए कहा कि उनके पास 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और वह सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और आगे भी उनके सम्मान व हितों के लिए निरंतर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को अटल शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसी दिन से 31 दिसंबर तक प्रदेश भर में सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे, जबकि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का अर्थ श्पारिवारिक दलों का गठबंधन है, जिसका स्वरूप उत्तर प्रदेश के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले कल्याण सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारियां दीं, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसा संगठन है जहां लोकतंत्र पूरी तरह कायम है। आवश्यकता के अनुसार टीम का गठन किया जाता है और पार्टी की जरूरतों के मुताबिक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है और इसी सिद्धांत के तहत काम किया जाता है। पार्टी किसी एक क्षेत्र को मजबूत करने के बजाय पूरे प्रदेश और देश के संतुलित विकास पर ध्यान देती है।

राजधानी में शीतलहर का कहर, नर्सरी व प्री-प्राइमरी स्कूल बंद

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर तक नर्सरी व प्री–प्राइमरी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जबकि कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं के समय मे परिवर्तन कर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंगलवार को जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्री–प्राइमरी और नर्सरी कक्षाओं में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक पूर्ण अवकाश रहेगा। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का संचालन समय परिवर्तित किया गया है।

संक्षिप्त

यूपी विधानसभा सत्र: सुरेश खन्ना बोले-सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर 7 साल कैद, एक करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन को लेकर सख्त कानून की व्यवस्था है और इसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने तथा सात वर्ष कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। खन्ना ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का प्रश्न उठाए जाने पर सदन को यह जानकारी दी। पटेल ने प्रश्न किया कि क्या प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अभद्र फोटो, वीडियो अपलोड की

रोकथाम की कोई योजना सरकार ने बनाई है और क्या सरकार ऐसे कार्य में लिप्त लोगों को चिह्नित कर दंडात्मक कार्यवाही के लिए कोई नीति बनाएगी? उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए दो मामलों का उदाहरण भी दिया, जिसमें एक ही तरह के मामलों में कार्रवाई में पुलिस ने भेदभाव किया। खन्ना ने मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बात की पूरी व्यवस्था की है कि इस विषय पर जागरूकता कैसे हो और जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायत मिले और शिकायत जिस स्तर की मिले, उस स्तर की कार्रवाई भी हो। मंत्री के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार से कहा, ''यह महत्वपूर्ण विषय है, इससे सभी लोग प्रभावित हैं और गलत सूचनाओं का दुष्प्रभाव होता है।'' उन्होंने कहा कि कोई योजना बनाकर जब तक इस तरह के अपराधियों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इसका संदेश नहीं जाएगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, ''समाज में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना गलत है लेकिन सरकार ने इसकी रोकथाम की व्यवस्था भी की है। इसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। सात साल तक की सजा है।'' मंत्री ने कहा, ''जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई बात आती है तो विशेष सचिव (गृह) को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें।''

इतिहास से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाना होगा : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में आयोजित 134वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर छात्र-छात्राओं को दिया मूलमंत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले: इतिहास की गलतियों का समय पर परिमार्जन जरूरी

शिक्षा संस्थान समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी के अनुसार, अनुशासन और परिश्रम से ही सफलता संभव, तकनीक साधन बने मगर जीवन पर हावी न हो

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेना आवश्यक है। इतिहास की गलतियों का समय पर परिमार्जन होना चाहिए, तभी समाज प्रगति करता है। यदि कहीं त्रुटि हुई है तो उसे सुधार करना होगा और अच्छे कार्यों को जीवन की प्रेरणा बनाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी परंपराओं को पर्व–त्योहारों के माध्यम से संजोकर रखा है। देश में राजनीति अपना काम करती रही, लेकिन राजे रजवाड़ों और समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में योगदान दिया। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में आयोजित 134वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने की मार्च पास्ट की तारीफ मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मार्च पास्ट के दौरान विद्यार्थियों का अनुशासन, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का जज्बा और समर्पण देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज के नौजवान देश की आजादी के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हों। उन्होंने कहा कि यह प्रयास सराहनीय है और इससे विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष कुंवर आनंद सिंह को, जिनके साथ मैंने कई बार इस संस्था के उन्नयन के बारे में चर्चा की। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। समाज को जोड़ने में शिक्षा संस्थानों की भूमिका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज को तोड़ने वाले तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों की होती है। वर्ष 1889 में जब इस संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब देश की परिस्थितियां कठिन रही होंगी। उसी कालखंड में वंदे मातरम् जैसे विचारों ने लोगों के मन में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी गुलामी को स्थायी मान लिया गया था, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंदमठ के माध्यम से वंदे मातरम् जैसी कालजयी रचना देश को दी। वर्ष 1896 में कांग्रेस के मंच से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे स्वर दिए जाने के बाद यह आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया।

भारत की विरासत पर आधारित हाउस प्रणाली की सराहना मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के लिए अजंता, नालंदा, तक्षशिला, सांची और उज्जैन जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के नाम पर हाउस बनाना भारत की गौरवशाली परंपरा को जीवित रखने का उत्कृष्ट प्रयास है। तक्षशिला दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक रहा, जहां ढाई हजार वर्ष पहले ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद और दर्शन की आधारशिला रखी गई। नालंदा की समृद्ध परंपरा, उज्जैन का खगोल ज्ञान और महाराज विक्रमादित्य का न्याय, अजंता और सांची की स्थापत्य विरासत आज भी भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक ऊंचाई का प्रमाण हैं। इन मूल्यों के आधार पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रयास सराहनीय है। ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़ा महत्वपूर्ण वर्ष मुख्यमंत्री योगी के अनुसार, यह वर्ष देश के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। गुरु तेगबहादुर जी की 350वीं शहादत, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 350वीं जयंती, वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होना देश के गौरवपूर्ण इतिहास की स्मृति कराते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने का उत्सव केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश ने दीपावली के माध्यम से इसे अपनाया। होली सामाजिक समता का पर्व बनी। रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे पर्वों ने समाज को जोड़ने का कार्य किया। हमारे पूर्वजों ने इन पर्वों को परंपरा के रूप में संरक्षित कर पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। बच्चों को दिया सफलता का मूलमंत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। नियमित पढ़ाई के साथ किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि से जुड़ना चाहिए। समय पर उठना, समय पर सोना और संयमित दिनचर्या स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से बचने की सलाह दी और कहा कि आधे घंटे से अधिक समय तक इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न करें।

भाषा व ज्ञान का विकास समाचार पत्रों और अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से होता है, इसलिए पढ़ने की आदत विकसित करने के साथ लाइब्रेरी में जाकर पौराणिक व ऐतिहासिक रचनाओं को पढ़ें। खेल, फिटनेस और तकनीक पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, पिछले 11 वर्षों में देश में खेलकूद को नई ऊंचाइयां मिली हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। हर गांव में खेल का मैदान और स्टेडियम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओपन एयर जिम और शारीरिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक के नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमें तकनीक को आत्मसात करना है। तकनीक हमारा वाहक बने, हमें तकनीक का वाहक नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में अवसर हैं, जिनके प्रति जागरूकता आवश्यक है। साथ ही, वैश्विक परिदृश्य में हो रहे उन्नयन कार्यों के प्रति भी अपडेट रहना चाहिए। कानाफूसी करने वालों से रहने की सलाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज में कुछ लोग भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कप और शील्ड देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले प्रमुख छात्र–छात्राओं में दिनेश प्रताप सिंह, प्रांजल त्रिपाठी, देवराज सिंह पटेल, आयुषी सिंह और सार्थक त्रिपाठी शामिल रहे। कार्यक्रम में 11 गोरखा राइफल्स के बैंड ने परेड में मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री तथा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन सिंह, पूर्व विधान परिषद सदस्य राकेश प्रताप सिंह, कॉलेज के प्रबंधक मनीष वर्धन सिंह, प्रबंध समिति के सदस्य विनय कुमार सिंह, राजा वीरेंद्र सिंह परमार, कॉलेज के शिक्षक, छात्र–छात्राएं व उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

एनसीएल ने सीएचपी रखरखाव एवं स्वच्छता केंद्रित 'वार्षिक रखरखाव एवँ स्वच्छता सप्ताह अभियान' का किया शुभारंभ

बृजेश चतुर्वेदी

सिंगरौली। सिंगरौली स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की अग्रणी अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक नवाचारी पहल के तहत आज से अपनी सभी परियोजनाओं में अवस्थित कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी) के रखरखाव एवं स्वच्छता पर केंद्रित 'वार्षिक रखरखाव एवँ स्वच्छता सप्ताह अभियान' का शुभारंभ किया । इस अभियान के अंतर्गत एनसीएल के सभी विभागीय सीएचपी, आउटसोर्सिंग सीएचपी सहित सभी एफएमसी परियोजनाओं का निरीक्षण निरीक्षक दलों द्वारा किया जा रहा है। एनसीएल मुख्यालय के निर्देशन में विद्युत और यांत्रिक और सीएचपी विशेषज्ञों की अलग अलग टीमों द्वारा कोल हैंडलिंग प्लांट्स का निरीक्षण किया जा रहा है । एफएमसी परियोजनाओं के रख रखाव और स्वच्छता के दृष्टिगत इस वार्षिक सप्ताह मनाने का उद्देश्य इनके रखरखाव एवं गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित करना है । इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएचपी परिचालकों / परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की भी योजना है । सूत्रों की माने तो इस हेतु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली में आगामी 29 दिसंबर 2025 किया जाएगा। गौरतलब है कि कोल हैंडलिंग प्लांट्स से सुरक्षित , स्वचालित और पर्यावरण अनुकूल विधि से खदानों से निकले कोयले का प्रेषण किया जाता है।

किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह : सपा

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, के मसीहा, गाँव, गरीब की आवाज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती शकिसान दिवसश के रूप में सपा जिलाध्यक्ष मोहम्मद कलीम खान के नेतृत्व में आयोजित किया गया इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कलीम खान एवं पूर्व विधायक कल्यान सिंह दोहरे ने कहा कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के किसान–पुत्र चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीण भारत और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। सयुस प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब हसन एवं विधानसभा अध्यक्ष कन्नौज पी पी सिंह वघेल ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि एक साधारण किसान परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने वाले चौधरी चरण सिंह अपनी बेमिसाल ईमानदारी, सिद्धांतों की दृढ़ता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश में

भूमि सुधारों को लागू किया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई नीतियां बनाईं, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन किया, जो आज भी प्रेरणादायक है, जब किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत हमें याद दिलाती है कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है. उनकी विचारधारा और संघर्ष हमें हमेशा ग्रामीण भारत की समृद्धि और सम्मान के लिए काम करने की प्रेरणा देते रहेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से सपा नेता विवेक पाल, सुनील दिवाकर, विधानसभा महासचिव आनंद बाबू यादव, सभासद आसिफ हुसैन सिद्दीकी, यशवीर भदौरिया, सतेंद्र दोहरे, गोविन्द कुशवाहा, तुफैल अहमद, दीपचंद्र, नितिन यादव, बी पी यादव, अभिषेक राजपूत, शिब्बू तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे।

गुजरात सरकार बोली- गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में अहम बदलाव; जानिए सबकुछ

एजेंसी

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराब सेवन के नियमों में ढील दी है। बदलावों के अनुसार अब गुजरात या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति नामित होटलों या रेस्तरां में पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इन परिवर्तनों की घोषणा की है। गुजरात में शराब को लेकर प्रतिबंध गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि, सरकार ने 2023 में गिफ्ट सिटी को छूट दी, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ केंद्रीय व्यावसायिक जिले में शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी। पिछली शर्तों को समाप्त किया गया नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गुजरात का निवासी नहीं है या विदेशी नागरिक नहीं है, अब जीआईएफटी सिटी में निर्दिष्ट स्थानों पर अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकता है। यह नया नियम पिछली शर्त को समाप्त करता है, जिसके तहत ऐसे बाहरी व्यक्तियों को अस्थायी परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। शराब सेवन के स्थान से संबंधित नियम में भी बदलाव गृह विभाग द्वारा लाया गया एक और बदलाव

शराब परोसने और सेवन करने के स्थान से संबंधित है। पहले, शराब का सेवन केवल गिफ्ट सिटी के भीतर शराब बेचने की अनुमति प्राप्त होटलों या रेस्तरां के निर्दिष्ट वाइन और डाइन क्षेत्रों में ही अनुमत था। अब लॉन, पूल के किनारे और छतों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी शराब का सेवन किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार, भोजन के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को रेस्तरां के वाइन और डाइनिंग क्षेत्र में बैठने की अनुमति है। अधिसूचना में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी के जिन कर्मचारियों के पास शराब पीने का परमिट है, वे निर्धारित स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों की मेजबानी कर सकते हैं, और अतिथियों को अस्थायी परमिट प्राप्त होंगे बशर्ते कि मेजबान कर्मचारी उनके साथ हो।

संक्षिप्त

भारतीय टीम से शुभमन को बाहर करना सही फैसला या चयन की अनिश्चितता? उथप्पा ने जताई चिंता, कैफ का अलग तर्क

एजेंसी / नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम चयन ने एक नई बहस छेड़ दी है। शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम से बाहर किए जाने पर जहां पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने चयन प्रक्रिया को अजीब और अस्थिर बताया, वहीं मोहम्मद कैफ ने साफ कहा कि शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के मामलों की तुलना करना गलत है। भारतीय क्रिकेट एक अजीब जगह बन गया है रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चौनल पर टीम चयन को लेकर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में अब कोई भी चीज तय नहीं लगती। उथप्पा ने कहा, श्भारतीय क्रिकेट३ यह एक अजीब जगह है। आप सोचते हैं कि चयन में कुछ तो स्थिरता होगी, लेकिन टीम घोषित होते ही सब उलट–पुलट हो जाता है। टीम खराब नहीं है, यह एक शानदार टीम है, लेकिन दिल टूटते हैं।

अंकुश जाधव का शानदार प्रदर्शन, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता

एजेंसी

भोपाल। नौसेना के किरण अंकुश जाधव

ने सोमवार को 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चौंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ओलंपियन अर्जुन बबूता की पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। जाधव ने 252.1 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया जबकि बबूता ने 251.4 अंक के साथ रजत पदक जीता। 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन के मौजूदा राष्ट्रीय चौंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 229.8 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। अर्जुन के रेलवे की टीम के साथी शाहू तुषार माने 209.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहे। हिमांशु (181.1), रामायण तोमर (166.7), ओंकार विकास वाघमारे (145.4) और प्रदीप सिंह (123.3) ने भी फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल जूनियर फाइनल में गुजरात के मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 254.3 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। पश्चिम बंगाल के अभिनव साव ने 251.6 अंक के साथ रजत पदक जीता जबकि ओंकार विकास वाघमारे ने 230.1 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया।

पूरी रात सो नहीं पाई, साढ़े तीन बजे उर्फी जावेद के साथ ऐसा क्या हुआ? पुलिस थाने पहुंचकर सुनाई आपबीती

एजेंसी

टीवी और सोशल मीडिया की चर्चित पर्सनालिटी उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका फैशन नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। बीते दिनों उर्फी के साथ ऐसी घटना घटी, जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। आधी रात उनके घर के बाहर दो अंजान लोगों की मौजूदगी और लगातार बेल बजाने की हरकत ने न सिर्फ उनकी नींद उड़ा दी, बल्कि उन्हें सुबह तड़के पुलिस थाने तक जाने पर मजबूर कर दिया। उर्फी के साथ हुई खौफनाक घटना घटना 22 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। उर्फी जावेद के मुताबिक, रात करीब साढ़े तीन बजे उनके घर की डोर बेल लगातार बजने लगी। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई

गलती से बेल बजा रहा होगा, लेकिन जब यह सिलसिला कई मिनटों तक नहीं रुका तो उनकी चिंता बढ़ गई। बाद में पता चला कि घर के बाहर एक नहीं बल्कि दो लोग मौजूद थे, जो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उर्फी ने बताया कि जब उन्होंने इंटरकॉम या दरवाजे के पास से उन लोगों से बात करने की कोशिश की और वहां से चले जाने को कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हालात उस वक्त और डरावने हो गए जब उन लोगों ने दरवाजा खोलने का दबाव बनाना शुरू किया। एक अकेली महिला के लिए यह स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उर्फी जावेद ने पुलिस को किया फोन हालात बिगड़ते देख उर्फी जावेद ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी दोनों शख्स का रवैया नहीं बदला। उर्फी के अनुसार, वो न सिर्फ उनके साथ बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी करते रहे और अपने किए से इनकार करते रहे। बार–बार 'निकल' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर माहौल और तनावपूर्ण बना दिया गया। बाद में जानकारी मिली कि दोनों लोग उसी बिल्डिंग में रहने वाले थे। इस पूरी घटना ने उर्फी जावेद को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई रात के तीन बजे किसी महिला के घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए कहे और मना करने पर भी वहां से न जाए, तो यह बेहद डराने वाला अनुभव होता है। खासतौर पर तब, जब महिलाएं अकेली रहती हों। उर्फी ने साफ शब्दों में कहा कि इस घटना के बाद वह खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। करीब 5 बजे पुलिस थाने पहुचीं उर्फी डर और तनाव के बीच उर्फी सुबह करीब 5 बजे पुलिस थाने पहुंचीं और पूरे मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पुलिस स्टेशन से अपनी तस्वीर साझा की और बताया कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे डरावना अनुभव रहा। उर्फी ने यह भी कहा कि वह जानना चाहती हैं कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उर्फी की बहन डॉली जावेद ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें बेहद घिनौनी हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। वहीं, फैंस और सेलेब्स भी उर्फी की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

क्या वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत विकास पथ पर बना रहेगा? आरबीआई ने दिया जवाब

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियाद और निरंतर आर्थिक सुधारों पर सरकार व नीतिगत संस्थानों का फोकस, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर बनाए रखने में मदद करेगा। वैश्विक व्यापार अनिश्चितता का दिखा असर रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार नीतियों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला, जहां कई देशों ने टैरिफ और व्यापार शर्तों पर द्विपक्षीय वार्ताओं का दोबारा रुख अपनाया। इन बदलावों का वैश्विक व्यापार प्रवाह और आपूर्ति शृंखलाओं पर असर अब भी उभर रहा है, जिससे वैश्विक विकास को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। आरबीआई ने माना कि भारत पूरी तरह से इन बाहरी झटकों से अछूता नहीं रहा, लेकिन मजबूत नीतिगत ढांचा और सुधारों पर जोर अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

महंगाई फिलहाल अनुकूल बना हुआ है रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई का परिदृश्य फिलहाल अनुकूल बना हुआ है, जिससे मौद्रिक नीति को विकास समर्थन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिली है। मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता को मजबूत करने और सुधारों को आगे बढ़ाने से दक्षता और उत्पादकता में सुधार होगा, जो भारत की विकास गति को और सुदृढ़ करेगा। शेयर बाजार को लेकर आरबीआई की राय वित्तीय बाजारों पर त्प् ने कहा कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में शेयर बाजारों में तेजी रही, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर बिग टेक कंपनियों को लेकर आशावाद था। हालांकि, हाल के महीनों में ऊंचे मूल्यांकन को लेकर चिंताओं के चलते बाजारों में कुछ हद तक जोखिम से बचने का रुख दिखा है। इसके साथ ही, उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो निवेश की रफ्तार भी धीमी पड़ी है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743